बिहार विधान परिषद

(198वां मानसून सत्र)

29 जुलाई 2021

[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह].

कुल प्रश्न 18

कार्यालय एवं आवास का निर्माण

*35 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि आरक्षी जिला नवगछिया में 'पुलिस-लाइन' के निर्माण कार्य में विलंब होने से सरकार का उद्देश्य बाधित हो रहा है जबकि निर्माण कार्य की शुरुआत कई वर्ष पहले से ही है;

(ख) क्या यह सही है कि अभी तक इस जिले में आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय तथा आवास हेतु स्थायी भवन का निर्माण नहीं हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वहां पर 'पुलिस-लाइन भवन' के निर्माण कार्य को गति देने के साथ-साथ आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय एवं आवास का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

मुआवजा का भुगतान कबतक

*36 **मो. फारूक (विधान सभा):**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला के पुरनहिया प्रखंड के अदौरी, बराही, खैरा पहाड़ी, दोस्तियां, कटैया, आशोपुर, बैरिया, पिपराही प्रखंड के पकड़ी, बकटपुर, इनरवा, माधोपुर, सिंगरहिया, रतनपुर, उकनी, देकुली धर्मपुर, मोहारी, कोपगढ़ आदि गांव बागमती तटबंध के बगल में रहने के कारण किसानों की जमीन तटबंध की मरम्मती हेतु दोनों तरफ काटकर गड्ढा बना दिया गया है जिसके कारण सैकड़ों एकड़ खेती प्रभावित हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त गांवों में तटबंध की दोनों तरफ ढाला का निर्माण नहीं होने के कारण लोगों को आने-जाने में कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार तटबंध की दोनों तरफ कटे मिट्टी की भराई एवं ढाला का निर्माण एवं किसानों के नुकसान हुए फसल का मुआवजा देने का विचार करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

दूसरे धंधों की व्यवस्था

***37 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

श्रम संसाधन :-

क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में हजारों रिक्शाचालक हैं जिनके स्वास्थ्य पर रिक्शा चलाने से बुरा प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या कोई ऐसी योजना सरकार के विचारार्थ है जिससे मनुष्य द्वारा रिक्शा चलाने की व्यवस्था को समाप्त किया जाय और बेकार होने वाले रिक्शाचालकों के लिए दूसरे धंधों की व्यवस्था की जाय ताकि वे अपना जीवनयापन मनुष्य की तरह कर सकें ?

टैक्स में कटौती कबतक

***38 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

वाणिज्य कर :-

क्या मंत्री, वित्त, वाणिज्य कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि पेट्रोल, डीजल की बढ़ी कीमतों में बड़ा योगदान राज्य सरकार द्वारा लिए जा रहे विभिन्न प्रकार के टैक्स का होना भी है;

(ग) क्या यह सही है कि अगर राज्य सरकार अपने टैक्स में कटौती कर दे तो आम लोगों को थोड़ी राहत मिल सकेगी;

(घ) क्या यह सही है कि पेट्रोल, डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण यातायात, खाद्य पदार्थों, साग-सब्जी भी महंगी हो गई है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बताएगी कि वह बिहार में प्रति लीटर कितना टैक्स लेती है तथा आम जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से क्या वह अपने टैक्सों में कटौती करेगी और नहीं तो क्यों ?

बैंक का स्थानांतरित कबतक

***39 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

वित्त विभाग :-

क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण जिले के भीतहां प्रखंड में एकमात्र राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा 'बैंक ऑफ इंडिया' है जो उत्तर प्रदेश के तमकुड़ी रोड में चलती है। यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शिक्षित बेराजगारों को उद्योग लगाने हेतु दिया जाने वाला ऋण योजना जो बेरोजगारों के लिए वरदान है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना फ्लाप है। 10 साल में एक भी योजना उद्योग नहीं लगा। इसे भीतहां प्रखंड में स्थानांतरित कराया जाय;

(ख) क्या यह सही है कि खंड (क) में वर्णित बैंक उत्तर प्रदेश के तमकुड़ी रोड में चलने के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग लगाने हेतु दिया जाने वाला ऋण योजना से उक्त प्रखंड के युवा वंचित हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त जिला के उक्त प्रखंड में लगभग 10 साल से एक भी योजना आधारित उद्योग नहीं लग सका है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (ख) में वर्णित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा को पश्चिम चम्पारण के भीतहां प्रखंड में स्थानांतरित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पईन की उड़ाही कबतक

***40 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

लघु जल संसाधन :-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि गया जिले के कंडी पंचायत अंतर्गत समदा पईन (किर्ती ढाबा के सामने) जो करीब पांच किलोमीटर लंबी है, कई वर्षों से उड़ाही नहीं होने के कारण उसका अस्तित्व समाप्त हो गया;

(ख) क्या यह सही है कि समदा पईन से हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी किंतु उड़ाही नहीं होने के कारण दर्जनों गांव के किसानों की फसल प्रतिवर्ष सूखे की भेंट चढ़ जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार समदा पईन की उड़ाही कबतक कराना चाहती है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

***41 श्री गुलाम रसूल (विधान सभा):**

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला अंतर्गत सिकटा प्रखंड की पंचायत कठिया मठिया के ग्राम- सेनुवरिया (वार्ड नं.- 13) में दो कट्ठा नौ धुर रकबा (खाता सं.- 7, खेसरा- 19) का कब्रिस्तान है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण उसमें जानवर मल-मूत्र त्याग करते हैं जिससे कब्रिस्तान की पवित्रता भंग होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना चाहती है ?

आहर एवं पोखर की मरम्मती

***42 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

लघु जल संसाधन :-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के वजीरगंज प्रखंड की सहिया पंचायत के ऐरू गांव के जंगल आहर, समरा आहर, गुहीबा पोखर एवं केसुरिया पोखर एवं पुनावा पंचायत का नौवा खाप आहर मरम्मती के अभाव में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त आहर एवं पोखरों से हजारों किसानों की भूमि सिंचित होती थी एवं आसपास का जलस्तर भी ठीक रहता था;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र इन आहरों एवं पोखरों की मरम्मती कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

नियुक्ति कबतक

***43 प्रो. (डा.) रामबली सिंह (विधान सभा):**

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन :-

क्या मंत्री, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि पर्यावरण एवं वन विभाग के पर्यावरण संभाग के योजनान्तर्गत विभागीय राज्यादेश सं. 6136, दिनांक- 7.11.1985 एवं राज्यादेश सं.- 1904, दिनांक- 31.03.1989 द्वारा सृजित पदों का अवधि विस्तार 2005-06 तक होता रहा;

(ख) क्या यह सही है कि पर्यावरण का महत्व दिनों-दिन विस्तार होने के कारण योजना से गैर योजना में स्थानान्तरण के बाद कुल- 17 पदों के लिए वित्त विभाग एवं मंत्री परिषद् से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में दिनांक- 01.03.2006 से विभागीय पत्रांक- वन पर्यावरण- 03/2005-337 (ई.)/प.व., दिनांक- 19.08.2006 द्वारा स्थायीकरण को स्वीकृति प्रदान की गयी है;

(ग) क्या यह सही है कि स्थायीकरण के 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा नियमित नियुक्ति नहीं की गयी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इन पदों पर नियमित नियुक्ति करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

उचित व्यवस्था कबतक

***44 श्री संजय प्रकाश (विधान सभा):**

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग (कारा), यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के 59 जेलों में 21 फीसदी से अधिक कैदी बंद हैं;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के सभी जेलों में 46,619 कैदी की व्यवस्था है, जबकि बंदी कैदियों की संख्या 56,424 है, महिला कैदी भी 2,047 की जगह 2,128 हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार की ओर से इन कैदियों को उचित व्यवस्था कबतक मिल सकती है, साथ ही कोरोना काल में ऐसी अव्यवस्था कितनी न्यायोचित है ?

आर्थिक सहायता कबतक

***45 सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

श्रम संसाधन :-

क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत राज्य में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजनालयों (एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज) की स्थापना की गयी है। इन नियोजनालयों का उद्देश्य बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उनमें विभिन्न प्रकार के कौशल विकास करना तथा उन्हें उपयुक्त रोजगार के लिए परामर्श देना है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में इन नियोजनालयों का एक प्रमुख उद्देश्य बेरोजगार लोगों को पंजीकृत करना और उन्हें रोजगार दिलाने के बाद उनकी संख्या का संकलन करना भी है। बहुत बड़ी संख्या में पढ़े-लिखे युवा, स्नातक पास युवाओं को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि राज्य में कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं और कितने लोगों को इन नियोजनालयों के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है, साथ ही जिन लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है, क्या राज्य सरकार उन्हें कोई आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहती है, अगर नहीं तो क्यों ?

आंगनबाड़ी की स्थापना

***46 श्री भीसम साहनी (विधान सभा):**

समाज कल्याण :-

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के प्रत्येक वार्ड में एक-एक आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की योजना है;

(ख) क्या यह सही है कि प. चम्पारण के बगहा नगर परिषद् की वार्ड संख्या 15 से 35 में एक भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, जिसके कारण वहां के महिलाओं एवं बच्चों को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त वार्डों में कबतक आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना कराना चाहती है ?

रोकथाम हेतु आवश्यक कार्रवाई

***47 श्री ललन कुमार सर्राफ (मनोनीत):**

गृह :-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में प्रत्येक जिला की जनसंख्या/क्षेत्रफल के आधार पर जिला बल पुलिस बल की नियुक्ति की जाती आ रही है;

(ख) क्या यह सही है कि मधेपुरा जिला की जनसंख्या/क्षेत्रफल के अनुसार पुलिस बल की काफी कमी है, जिसके कारण आये दिन अप्रिय घटनाएं एवं चोरी, राहजनी, लूट की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधेपुरा जिला में अप्रिय घटनाओं एवं चोरी, लूट, राहजनी की रोकथाम हेतु आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पुनर्वास की व्यवस्था

***48 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

समाज कल्याण :-

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार के 6464 गुमशुदा बच्चे दूसरे राज्य के बाल गृह में रहने को मजबूर हैं;

(ख) क्या यह सही है कि पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण ये बच्चे दूसरे राज्य के बाल गृह में रह रहे हैं जबकि राज्य के मानवाधिकार आयोग ने उन बच्चों को अभियान चलाकर लाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है, इसके बावजूद भी बच्चे को अपने राज्य में नहीं लाया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अभियान चलाकर उक्त बच्चों को अपने राज्य में ला करके उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

राहत और बचाव कबतक

*49 **श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

जल संसाधन :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि उत्तर बिहार की कई नदियों के जल स्तर में वृद्धि से बड़े भूभाग में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि बाढ़ के कारण कई स्थानों पर आम जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोगों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि बाढ़ की संभावित विभीषिका के बावजूद समय पूर्व आवश्यक कदम उठाने में कोताही बरती गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बताएगी कि बाढ़ से राहत और बचाव दिलाने हेतु उसने कौन-कौन से कदम उठाए हैं, नहीं तो क्यों ?

गाड़ियों की नीलामी कबतक

*50 **श्री ललन कुमार सर्राफ (मनोनीत):**

वित्त विभाग :-

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि सरकारी विभागों में सरकारी गाड़ियां वित्त विभाग के निदेशानुसार उपलब्ध करायी जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकारी विभागों में उपलब्ध करायी गयी गाड़ियां खराब हो जाने पर संबंधित विभाग के परिसर में यत्र-तत्र सड़कों पर डम्प कर दी जाती हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त गाड़ियां मरम्मती के योग्य न होने के कारण इनकी नीलामी की अति आवश्यकता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वित्त विभाग के निदेशानुसार विभिन्न विभागों के परिसर में यत्र-तत्र सड़कों पर डम्प की हुई गाड़ियों की नीलामी करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

शैक्षणिक एवं आर्थिक सुधार कबतक

*51 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण :-

क्या मंत्री, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के करीब सभी प्रखंडों में जहां तहां डोम बिरादरी के लोग सड़क के किनारे या बांध पर रहते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इस बिरादरी के लोग शादी-विवाह एवं पर्व-त्योहार में उपयोग होने वाले बांस की सामग्री का निर्माण कर अपनी जीविका चलाते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि आजादी के सात दशकों के बाद भी इनमें शैक्षणिक एवं आर्थिक सुधार नहीं हो पाया है जिस कारण इस बिरादरी के लोग अपने को राज-विहीन नागरिक मानते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इस बिरादरी के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक सुधार के के लिए सरकार के द्वारा अबतक योजना नहीं बनाये जाने का क्या औचित्य है ?

तैयारी तथा भूमिका का निर्धारण

*52 **श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन :-

क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के कार्बन उत्सर्जन को घटाने को लेकर बिहार सरकार द्वारा कहीं कोई प्रतिबद्धता नहीं की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार को कम कार्बन उत्सर्जन की तरफ ले जाने की दिशा में सरकार के पास कोई ऐक्शन प्लान नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य के पास कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ने पर होने वाले खर्च के वहन के क्रियान्वयन को लेकर अनिश्चितता व्याप्त है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यह बतलाएगी कि इस संबंध में वह क्या करने जा रही है तथा अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की तैयारी तथा भूमिका का निर्धारण क्या किया गया है, नहीं तो क्यों ?